



# INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

## Challenges of Financial Inclusion and Financial Literacy

### वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता की चुनौती

श्रीमती इन्दु आसेरी

सह -आचार्य अर्थशास्त्र

राजकीय महाविद्यालय ,आबु रोड़

जिला- सिरोही ।

#### साराशं

किसी भी देश के आर्थिक विकास का मुख्य आधार उस देश का बुनियादी ढाँचा होता है। यदि बुनियादी ढाँचा ही कमजोर हो तो कितना भी प्रयास किया जाए व्यवस्था को मजबूत नहीं बनाया जा सकता है। यही कारण है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विकास एवं उन्नति हेतु किये जाने वाले प्रयासों को बल प्रदान करने के एक लिये नीति निर्माताओं द्वारा एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जाता है जिसके माध्यम से सरकार आम आदमी को अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम में शामिल कर सके। वित्तीय समावेशन की पहुँच बिना किसी रुकावट के विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक करने के लिये सरकार द्वारा 'डिजिटल भारत' अभियान प्रारंभ किया गया। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की नींव रखी गई। वित्तीय समावेशन और डिजिटल भारत के सम्मिलित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये ही, जैम त्रयी (जनधन-आधार-मोबाइल) की आधारशिला रखी गई। वैश्विक महामारी Covid-19 के दौरान जरूरतमंदों तक सरकारी सहायता पहुँचने में जैम त्रयी की भूमिका सराहनीय रही है। वित्तीय समावेशन को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि वित्तीय साक्षरता का समुचित प्रसार हो और वित्तीय समावेशन के वाहक ऐसे व्यक्तियों को रखा जाए जिन्हें ग्रामीण जनता और बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों की आर्थिक जरूरतों व ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समुचित जानकारी हो। तभी, वह वित्तीय समावेशन के मूल उद्देश्यों को वंचित आबादी तक क्रियान्वित कर सकता है।

कीवर्ड - आर्थिक विकास , वित्तीय समावेशन, जैम त्रयी

**वित्तीय शिक्षा से तात्पर्य** - बचत, निवेश, ऋण और व्यय के बारे में जानकारी, ज्ञान और कौशल हासिल करना, व्यक्तिगत वित्त को प्रबन्धित करने के लिये आवश्यक ज्ञान को वित्तीय साक्षरता कहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि इसके लिये वित्त के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान की जाये, बल्कि यह तो ऋण को उत्तरदायित्व पूर्ण तरीके से समझने, मुद्रा को प्रबन्धित करने, वित्तीय जोखिमों को न्यूनतम करने तथा बचतों से दीर्घकालीन लाभ प्राप्त करने जैसे विविध पहलुओं को समाहित करती है। दूसरी ओर वित्तीय शिक्षा को व्यापक रूप से वित्तीय बाजार उत्पादों, विशेष कर सुसूचित चयन करने के लिये प्रतिफल तथा जोखिमों की जानकारी रखने एवं समझने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से वित्तीय साक्षरता प्राथमिक रूप से

व्यक्तिगत वित्तीय शिक्षा से सम्बन्ध है, ताकि व्यक्ति अपने कल्याण में सुधार लाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने योग्य हो जाये और वित्तीय मामलों के कष्टों से बच सके।

ग्रामीण समाज की मानसिकता में बदलाव का हमारा नजरिया इस तथ्य पर आधारित है कि यह समाज अलगाव की विशेषता लिये हुए होता है, अतः इसकी प्रादेशिक आत्मनिर्भरता के चारों ओर आर्थिक विशेषतायें विकसित हो जाती हैं। संस्कृति का स्वरूप भी क्षेत्रीय होता है तथा यह स्थानीय वातावरण से विकसित होता है। ग्रामीण समाज को चयनित गुणों का भी विकास कर लेता है। कोई भी ग्रामीण समाज जितना अलगाव में होगा, उतनी ही यह विशेषतायें स्पष्ट होंगी। उत्पादन में व्यापारीकरण तथा विशिष्टीकरण प्रारम्भ हो जाने से ऋण केवल उपभोग तक ही सीमित न रहकर उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहन करने लगती है। ग्रामीण समुदाय के सामाजिक जीवन की जीवंतता घटने लगती है तथा आर्थिक एवं सामाजिक वर्गों के मध्य संघर्ष बढ़ता है।

ग्रामीण शिष्टाचार अब भौतिकवादी हो गया है। समर्पित शिक्षक एवं उत्तरदायी बुजुर्ग लगभग समाप्त हो चुके हैं। भौतिक उत्थान के साथ-साथ जीवन मूल्य भी परवर्तित हो रहे हैं। वैकल्पिक रूप से कुछ निर्धारित मानदण्डों के चारों ओर की वस्तुओं के विस्तृत प्रयोग से ऐसा हो रहा है। बढ़ते शिक्षा स्तर तथा कृषि क्षेत्र से बाहर रोजगार के अवसरों के कारण गावों में संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हो रहा है। गांव के गरीब लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग होने से गांव के स्थानीय लोगों से पीड़ियों पुराने सम्बन्धों को तोड़ रहे हैं। परम्परागत सम्बन्धों को तोड़कर स्वामी-सेवक सम्बन्ध भी बदल गये हैं। रोजगार की तलाश करने हेतु गावों के बाहर रहने के कारण गांव के आदमी की शहर की ओर प्रवास करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उनका सोचना है कि उनकी पसन्द मनोरंजनात्मक सुविधाओं के कारण एक कस्बा अथवा शहर उनके रहने के लिये एक सुखी स्थान है।

यदि देश की समस्त आबादी को विभिन्न वित्तीय गतिविधियों तथा विकासपरक कार्यक्रमों से जोड़ना है तो वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में हमें दृढ़ निश्चय के साथ काम करना होगा। इस दिशा में कार्य करने के लिए बैंकों को सबसे पहले उन कारणों को दूर करना होगा जिनकी वजह से कमजोर, उपेक्षित, वंचित एवं कम आय वर्ग के लोगों तक बैंकिंग सुविधाएँ नहीं पहुँच पायी है। हालांकि इन सभी के पीछे हमारे देश की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियाँ भी जिम्मेवार हैं।

**भौगोलिक कारण** - हमारे देश की भौगोलिक संरचना, आबादी का असमान वितरण, गांवों में आधारभूत संरचना का अभाव इत्यादि कारणों से बैंकों के लिए हर जगह शाखाएँ खोलना संभव नहीं है।

**सामाजिक कारण** - सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के बीच वित्तीय शिक्षा तथा वित्तीय उत्पादों की जानकारी का घोर अभाव रहता है।

**आर्थिक कारण** - कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण ग्रामीण एवं शहरी गरीब बैंक खाते खोलने के लिए इच्छुक नहीं होते। ऐसे में बैंकों से उपलब्ध साख सुविधाओं के अभाव में वे स्थानीय साहूकारों से मंहगे दरों पर ऋण लेने के लिए मजबूर होते हैं।

**वित्तीय संस्थाओं की कमियाँ** - बैंकों का यह मानना है कि देहाती क्षेत्रों में उपेक्षित / वंचित वर्गों तक बैंकिंग सुविधाओं का पहुँचाना लाभकारी नहीं है जो कि सही नहीं है। बल्कि इसके पीछे मुख्य रूप से बैंकों का उच्च परिचालन व्यय, जागरुकता की कमी, अनुपयोगी बैंक उत्पाद, भाषागत समस्याएँ और कर्मचारियों का असहयोगात्मक रवैया इत्यादि कारक जिम्मेवार हैं।

उपरोक्त समस्याओं के मद्देनजर बैंकों द्वारा शाखा नेटवर्क की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेवाओं को समाज के सभी वर्गों तक पहुँचाने में होनेवाली कठिनाईयों से निपटने, समाज एवं बैंकों के बीच सहजता लाने हेतु बैंकों द्वारा कारोबार सुविधादाता (बीएफ) / कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया गया। बैंकिंग उद्योग जगत में बीसी-बीएफ एक नई संकल्पना है, किंतु प्रचलन में पुरानी है। इस

संकल्पना का सरोकार कारोबार के स्पष्टीकरण और महत्व से है। आज विश्व के कई देश निवेश प्रणाली की प्रक्रिया अपनाने के लिए आम जनता को बैंकिंग कारोबार से जोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। निम्नलिखित बिंदुओं से हम वित्तीय साक्षरता के प्रसार में बीसी - बीएफ की भूमिका का आकलन कर सकते हैं -

1. वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में - वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को वित्तीय साक्षरता व जागरूकता से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बीसी - बीएफ बैंक व ग्राहक के बीच संपर्क साधन बनकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में भरपूर सहायता कर सकते हैं।
2. आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर - बीसी - बीएफ वित्तीय साक्षरता द्वारा गरीबों को बचत योजनाओं, विभिन्न बैंकिंग सेवाएं, उत्पादों का बाजार में विपणन इत्यादि के बारे में जानकारी देकर उन्हें स्वावलंबी बना सकते हैं।
3. कम वित्तीय साक्षरता से आर्थिक विकास में रुकावट - वित्तीय साक्षरता गरीब लोगों को अपने परिवार, गाँव, शहर व देश के विकास हेतु सशक्त बनाने का सबसे उपयुक्त साधन है। बीसी - बीएफ ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन व उसे प्राप्त करने के स्रोत, बैंक ऋण सुविधा, सब्सिडी, पूंजी इत्यादि की जानकारी प्रदान कर देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकते हैं।
4. वित्तीय उत्पादों की जटिलता - वित्तीय साक्षरता की सहायता से आम आदमी को आसानी से जटिल स्वभाव वाले वित्तीय उत्पादों के बारे में समझाया जा सकता है। इसके प्रसार से वह योजना व उत्पादों की अच्छाई व बुराई के बारे में स्वयं निर्णय ले सकता है।
5. ग्राहक प्रसार - बैंक विविध तरीकों द्वारा अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं लेकिन यह तभी संभव होगा, जब बैंकिंग और ग्राहक के बीच वित्तीय संवाद स्थापित होगा। इस कार्य में बीसी - बीएफ महत्वपूर्ण सहयोग कर सकते हैं।

**वित्तीय साक्षरता और आर्थिक सहायता का परिचय** - अपना रोजगार लगाने के लिए सरकार द्वारा कई रियायतें व आर्थिक सुविधाएं दी जाती हैं। ये सहायता या आर्थिक सहयोग, उद्योग केंद्रों, वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों के माध्यम से दिये जाते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरांत बैंकों ने सामाजिक उत्थान के लिए अनेक कार्य किये हैं। इन कार्यों में समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के लिए तथा महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। आज देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी सरकार द्वारा अनेक योजनाएं तैयार की गई हैं जो बैंकों के माध्यम से व अन्य कई अभिकरणों के माध्यम से चलाई जा रही हैं, परंतु इन योजनाओं की पर्याप्त जानकारी अधिकांश महिलाओं को नहीं है। यदि हम वित्तीय साक्षरता के माध्यम से समस्त महिलाओं तक ये सूचनाएं पहुंचा सकें तो नारी सशक्तीकरण संभव हो जाएगा।

### वित्तीय साक्षरता के उद्देश्य-

वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार करना वित्तीय साक्षरता का प्रमुख उद्देश्य है। इसी के साथ कुछ अन्य उद्देश्य बताए जा सकते हैं-

1. वित्तीय रूप से वंचित लोगों को वित्तीय रूप से साक्षर करना।
2. मात्र धन व्यवहार को ही प्राधान्य न देते हुए धन प्रबंधन को बढ़ावा देना।
3. अपनी आवश्यकताओं तथा उपलब्ध सेवा/उत्पादों का योग्य उपयोग करना।
4. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग सेवाओं तथा उत्पादों के प्रति शिक्षित करना।
5. ऋण प्राप्त करने हेतु तथा उसके योग्य उपयोग के लिए वित्तीय परामर्श देना।

## वित्तीय साक्षरता के मार्ग में व्याप्त समस्याएँ-

वित्तीय साक्षरता का मुख्य उद्देश्य वित्तीय रूप से वंचित लोगों को वित्तीय साक्षर करना रहा है। इस मार्ग में अनेक समस्याएँ हैं जिसे निम्नरूपसे स्पष्ट किया जा सकता है -

1. योग्य योजनाओं तथा राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव।
2. ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों मूलभूत सुविधाओं का अभाव।
3. लोगों में निरक्षरता या बहुत ही कम पढ़ा-लिखा होना।
4. संपूर्ण देश के लिए समान शिक्षा नीति का अभाव।
5. सक्षम रोजगार योजनाओं का अभाव।
6. बैंकिंग सेवाओं का ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में विस्तार न किया जाना।
7. क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा हिन्दी का समुचित उपयोग न किया जाना।
8. सूचना प्रौद्योगिकी की सरल प्रणाली का उपयोग न किया जाना।

## वित्तीय साक्षरता की सफलता के लिए आवश्यक प्रयास -

वित्तीय साक्षरता को सफल बनाना वित्तीय समावेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए कुछ निम्नलिखित प्रयास करना जरूरी हो जाता है-

- सरकार द्वारा वित्तीय साक्षरता के प्रचार हेतु जनमानस में जागरूकता लाने के लिए शिक्षाप्रद तथा प्रोत्साहनप्रद अभियान चलाया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा देश की समस्त शिक्षा संस्थाओं में माध्यमिक स्तर से ही वित्तीय साक्षरता हेतु बुनियादी वित्तीय आवश्यकताओं पर अनिवार्य रूप से अध्ययन शुरु किया जाना चाहिए।
- सरकार को डाकघरों जैसे विशाल नेटवर्क को वित्तीय साक्षरता अभियान हेतु उपयोग में लेना चाहिए।
- बैंकिंग सेवाओं के उपयोग के विषय में जागरूकता लाना।
- लोगों को ऋण से संबंधित उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक बनाना।
- लोगों में बचत की आदतों का विकास करना।

वित्तीय साक्षरता के सफलता का प्रमुख लाभ यह होगा की हमारी अर्थव्यवस्था के अंतिम व्यक्ति को इस व्यवस्था से जुड़ने का अधिकार मिलेगा, उसकी वित्तीय बुद्धिमत्ता का विकास तथा निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी, मुद्रा के लेन-देन के साथ ही उसके योग्य प्रबंधन की क्षमता प्राप्त होगी, वित्तीय तथा बैंकिंग सेवाओं की मांग का सृजन होगा, उन्हे ऋणग्रस्तता के संकट से बाहर आने हेतु अभिप्रेरणा मिलेगी, बचत करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी तथा बचत का योग्य उपयोग होगा, बैंक को भविष्य का मूल्यवान ग्राहक प्राप्त होगा।

## वित्तीय साक्षरता, कार्यविधि एवं मानसिकता में बदलाव -

- वित्तीय साक्षरता के प्रति सरकार तथा अन्य पुण्यधारियों की प्रतिबद्धता के दिये हुए होने पर इन कार्यक्रमों की प्रभावोत्पादकता तथा कुशलता का निर्धारण करना महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि यह समझा जा सके कि गांवों में क्या विधि काम करती है और क्या नहीं। भारत जैसे विविधतापूर्ण ग्रामीण समुदाय के विकासगत दर्शन में रोज हजारों फूल खिलते हैं। अतरू सर्वोत्तम व्यवहारों को दिखाने से

पहले इन आधारभूत परीक्षणों का एक सर्वेक्षण किया जाये, विशेषकर हमें एक ओर वित्तीय साक्षरता तथा दूसरी ओर वित्तीय समावेशन तथा सुधरे हुए वित्तीय परिणामों के बीच के सम्बन्धों का अध्ययन करना चाहिये, ताकि यह समझ सके कि कौन सा मॉडल कुशल एवं प्रभावशाली रहा है।

- वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के लिये प्रशिक्षित निर्देशकों/सलाहकारों की आवश्यकता है। ये सलाहकार उसी स्थिति में सर्वाधिक कुशल सिद्ध होंगे, जब वे इन ग्रामीणजनों के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने के समय उपलब्ध रहेंगे। वित्तीय साक्षरता को लाभदायक एवं प्रासंगिक बनाने के लिये वित्तीय सेवाओं की उपयुक्त समय पर जानकारी महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में गैर-सरकारी एजेन्सी के सफल परीक्षण का अध्ययन करना लाभदायक होगा।
- वित्तीय साक्षरता के विकास को बढ़ावा देने हेतु प्रौद्योगिकी में काफी सम्भावनायें निहित हैं - एक तो प्रदायक माध्यम (Internet) तथा दूसरे सीखने की प्रक्रिया के अंतरंग भाग (निर्देशात्मक कम्प्यूटर) के रूप में तकनीकी गावों में तथा दूरस्थ स्थलों पर रहने वाले लोगों के बीच दूरी को भी पाट सकती है। वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में इन ग्रामीणों को शामिल करने तथा उनके सशक्तीकरण करने के तौर-तरीके के रूप में हम तकनीकी का कैसे सर्वोत्तम प्रयोग कर सकते हैं ? यह मानते हुए कि लोग सूचनाओं को विभिन्न तरीकों से प्राप्त करते हैं, सीखते भी हैं तथा पचाते भी हैं, लोगों के ध्यान और आकर्षण को ग्रहण करने के सर्वोत्तम तरीकों को निर्धारित करने के लिये संवाद के सभी सम्भावी तौर-तरीकों का सर्वेक्षण करना चाहिये।

ग्रामीण जनता की मानसिकता के बदलाव के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्तीय असाक्षरता ग्रामीण समुदाय को रूग्ण करती है, यद्यपि विभिन्न तरीकों से इंग्लैण्ड, अस्ट्रेलिया आदि कई देशों में हुए सर्वेक्षणों से पता चला है कि काफी लोग बिना समझे-बूझे वित्तीय जोखिम ले रहे हैं और वास्तव में देखा जाये तो वे मुद्रा के नासमझ प्रबन्धक हैं। इस बात पर भी समुचित रूप से विश्वास किया जाता है कि वित्तीय साक्षरता अथवा वित्तीय सेवायें प्रदान करने वाली मॉडल कोडबुक्स में वित्तीय साक्षरता द्वारा लायी जाने वाली पारदर्शिता की कमी के कारण ही हाल ही का वित्तीय संकट इतने व्यापक रूप से फैला है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुबिक्री तथा ग्राहकों द्वारा इन सौदों के जोखिम तत्व को समझे बिना किये गये अनुबन्धों के ढेर सारे उदाहरण मिलते हैं, जिससे अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव तथा गैर टिकाऊ व्यवसाय देखने को मिले।

वित्तीय साक्षरता की राह में बाधाएं -

- कड़ी निगरानी के बावजूद आए दिन बड़ी संख्या में कंपनियाँ दिवालिया हो जाती हैं, या जान-बूझकर योजनाबद्ध तरीके से लोगों की मेहनत की कमाई लेकर चंपत हो जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त गैर बैंकिंग कंपनियों की मौजूदा संख्या लगभग 11753 है। जबकि 1554 कंपनियों का कोई अता-पता नहीं है। इनके अलावा 1000 से अधिक कंपनियों को गैरकानूनी लेन-देन के कारण प्रतिबंधित करना पड़ा है। अर्थात् भारत में लगभग 22 प्रतिशत कंपनियाँ धोखेबाज निकलती हैं, जो एक बहुत बड़ा आँकड़ा है। लाखों लोगों को जिन्दगी भर की जमापूँजी से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे में वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को पूरा करने के नाम पर माइक्रो वित्त कंपनियों या चिट फंड कंपनियों को बढ़ावा देने के निर्णय को लोग संदेह की नजर से देख रहे हैं।
- भारत के गाँवों में प्राचीन काल से ही महाजनों का बर्चस्व रहा है, जो किसानों को पहले उदारता से कर्ज देते थे और फिर मनमाना ब्याज वसूलते थे। कर्ज बढ़ता जाता था, अंत में किसान के खेतों पर महाजन का कब्जा हो जाता था, जिस पर किसान बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर हो जाता था। अब बैंकों को गाँवों में व्यवसाय प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार मिला है। इसके लिए वे महाजन वर्ग

के ही किसी सदस्य को योग्य पाएंगे, और इससे वही पुराना शोषक वर्ग फिर से शक्तिशाली बनेगा, जिससे ग्रामीणों को बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीयकृत बैंकों को सौंपी गई थी।

- पिछले कुछ वर्षों में भारत में लाखों किसानों ने आत्महत्या की है। जोशी अधिकारी संस्थान की हाल ही में प्रकाशित सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि उन किसानों ने बैंकों से कर्ज लिया था, जिसे फसल खराब होने के कारण वे चुका नहीं पा रहे थे। ऐसी स्थिति में बैंकों के वसूली एजेंटों की धमकियों और सख्त एवं अपमानजनक कार्रवाइयों ने किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। इन घटनाओं से गरीब आबादी की मानसिकता बैंक और खासकर उनके कर्ज से दूर रहने की बन गई है। उनकी झिझक को मिटाना इतना आसान नहीं होगा, जबकि वित्तीय समावेशन की सफलता के लिए उनकी ओर से वित्तीय उत्पादों की माँग उठनी जरूरी है। भूमंडलीकरण, उदारीकरण और उसे लागू करने वाली बैंकिंग व्यवस्था की छवि गरीब विरोधी और शोषणकारी बन गई है, जिसे सुधारना जरूरी है।
- आम तौर पर बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय समावेशन या साक्षरता अभियान के लिए जो आयोजन किए जा रहे हैं, वे आयोजन धर्मिता का शिकार हो रहे हैं। धमाकेदार आयोजन करके उसकी तत्परता से रिपोर्टिंग कर दी जाती है। किसी तरह धर-पकड़ कर गरीबों के खाते खुलवा कर शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन हो जाने का दावा ठोंक दिया जाता है। बैंकों और अन्य संस्थाओं के सामने भी लाभप्रदता के अलावा सीमित कर्मचारी बल की मजबूरी है

वित्तीय साक्षरता की राह में आ रही बाधाओं के निवारण के उपाय:-

- वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में सभी गैर बैंकिंग संस्थाओं को भागीदारी बनाने के बजाय अच्छी संस्थाओं के चुनाव की रणनीति अपनाई जाए।
- व्यवसाय प्रतिनिधियों और व्यवसाय सहायकों का चुनाव करते समय वंचित तबकों के योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाए।
- वसूली एजेंटों की बहाली की पद्धति को समाप्त किया जाए और सरकारी एजेंसियों को इस काम के लिए सक्षम बनाया जाए।
- वित्तीय समावेशन अथवा वित्तीय साक्षरता के कार्यों की प्रगति अथवा लक्ष्यों को पूरा करने संबंधी संस्थाओं के दावों की निगरानी अथवा जाँच की प्रभावी प्रणाली विकसित की जाए।
- सभी प्रकार की जानकारियाँ, रिपोर्ट, नियमावली, प्रचार सामग्री आदि मूल रूप से हिंदी में तैयार कराई जाए। भारतीय भाषाओं के वाक्य विन्यास एवं शब्दावली में अधिक समानता होने के कारण हिंदी में उपलब्ध सामग्री को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करके प्रयोग करना विभिन्न भाषायी क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के लिए अधिक आसान होगा।
- हर हाल में ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता एवं समावेशन का संपूर्ण काम स्थानीय भाषाओं के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। निजी या सरकारी दोनों ही क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को राजभाषा नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया जाए। क्योंकि गरीब और निरक्षर ग्रामीणों के साथ बराबरी के स्तर पर संवाद कायम करके ही उन्हें मानसिक ग्रंथियों एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त कर पाना संभव होगा, जिसके बिना वित्तीय साक्षरता का काम अधूरा रह जाएगा।

संदर्भ -

- मेहरोत्रा निरुपम, "वित्तीय समावेशन-एक अवलोकन", आर्थिक विश्लेषण और अनुसंधान विभाग, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई, 2009
- दीपाली पंत जोशी, "वित्तीय समावेशन, चुनौतियाँ एवं अवसर" भारिबैं बुलेटिन सितंबर 19, 2014
- शक्तिकान्त दास, "वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-25" भारिबैं बुलेटिन जनवरी 2021